

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 01

अंक – 343

बेमेतरा, बुधवार 30 जुलाई 2025

रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित

कुल पेज – 8

मूल्य – 5 रुपये

पहला कॉलम

बिहार में डॉंग बाबू नाम के कुत्ते ने बनवा लिया आवासीय प्रमाण पत्र, जांच शुरू

पटना। बिहार की राजधानी पटना में एक कुत्ते के नाम से आवासीय प्रमाणपत्र जारी हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया है। मसौढ़ी अंचल में डॉंग बाबू नाम से प्रमाणपत्र जारी हुआ है, जिसमें पिता का नाम कुत्ता बाबू और मां का नाम कुतिया देवी लिखा है। प्रमाणपत्र में फोटो के स्थान पर कुत्ते की तस्वीर लगी हुई है। प्रमाणपत्र 24 जुलाई को जारी किया गया है। मामले को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब सरकार और प्रशासन की किरकिरी होने लगी तो पटना जिला प्रशासन ने इसका जवाब दिया है। एक्स पर लिखा, मसौढ़ी अंचल में डॉंग बाबू के नाम से निवास प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है। आवेदक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी को विस्तृत जांच कर 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दोषी कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।

बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में बिजली का कंरट फैलने से भगदड़, 2 की मौत

बाराबंकी। उत्तराखंड में मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी बिजली का कंरट फैलने से भगदड़ मच गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। घटना अवसानेश्वर मंदिर में तड़के 3 बजे घटी है। मृतकों में 22 और 25 वर्षीय दो युवक शामिल हैं। इसके अलावा 38 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि अब हालात सामान्य है। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। श्रद्धालुओं ने बताया कि सोमवार को अवसानेश्वर मंदिर में काफी भीड़ थी। यहां बारिश से बचने के लिए टीन शेड लगाया गया है। सोमवार तड़के बंदरों ने टीन शेड के ऊपर गए बिजली के तारों को तोड़ दिया। तार टीन शेड और मंदिर के मुख्य गेट पर गिरा, जिससे कंरट उतर आया। कंरट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में 28 लोग घायल हुए हैं।

लगभग 14 राज्यों में झूमके बरसंगे बादल, राजस्थान के 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

नईदिल्ली। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर के कारण देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। कई जगह बाढ़ के हालात हैं। बांधों में पानी झलकने लगा है और नदियां खबरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 28 जुलाई को राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में कई इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। इस दौरान 2-6 इंच तक बरसात हुई। साथ ही झालावाड़ में बिजली गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई।

देवघर में सावन सुबह पर पसरा मातम का अंधेरा...

एक साथ...हुई 18 कांवड़ियों की मौत, श्रद्धालुओं का दर्दनाक अंत

नई दिल्ली/ एजेंसी

झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में गोड्डा-देवघर मुख्य मार्ग पर मंगलवार, 29 जुलाई की सुबह एक बस और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में कम से कम 18 कांवड़ियों (तीर्थयात्रियों) की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि झारखंड के देवघर जिले में मंगलवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में कम से कम 18 कांवड़ियों की मौत हो गई। साथ ही, कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। दुबे ने एक पोस्ट में कहा, मेरे लोकसभा क्षेत्र देवघर में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक की टक्कर में 18 श्रद्धालुओं की जान चली गई। बाबा बैद्यनाथ जो उनके परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हालांकि, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में पाँच कांवड़ियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि घायलों की हालत गंभीर होने के कारण हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। इस बीच, यातायात पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि दुर्घटना में कम से कम नौ लोगों की



मौत हो गई है और घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि कांवड़ियों को ले जा रही एक बस मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया जंगल के पास तड़के करीब साढ़े चार बजे गैस सिलेंडर ले जा रहे एक वाहन से टकरा गई। दुमका क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, “‘‘देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया जंगल के पास कांवड़ियों से भरी 32 सीट वाली बस और गैस सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हालांकि, यातायात

पीएम मोदी ने सड़क हादसे में कांवड़ियों की मौत पर जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड के देवघर में हुए सड़क हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।



प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि झारखंड के देवघर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुःख है। इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें यह दुःख सहन करने की शक्ति दें। साथ ही, मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश

मंडी में बादल फटने से फिर बरपा कहर,तीन लोगों की मौत,मलबे में दबीं कई गाड़ियां.....

मंडी/ एजेंसी

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश ने फिर तबाही मचाई है। बादल फटने से इस बार मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर कहर बरपा है। मंडी शहर के जेल रोड में अभी तक तीन लोगों की पानी के बहाव में बहने से मौत की पुष्टि हुई है। एक महिला का शव मलबे में दबी गाड़ियों के बीच में फंसा

हुआ था, जिसे कड़ी मशक़त के बाद बाहर निकला गया। मलबे में फंसे कई लोगों को खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया। मंडी सदर क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद रखने का फैसला लिया गया। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में दर्जनों छोटे-बड़े वाहन मलबे में दब गए हैं और कुछ बह गए हैं। इसके अलावा पैलेस कॉलोनी, जोनल अस्पताल



और अन्य स्थानों पर बारिश बचाव एवं राहत कार्य चलाया जा रहा है। मृतकों के आसुओं की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि संघर्ष के बीच अचानक ऑपरेशन क्यों रोक़ा गया? प्रियंका ने सवाल उठाया कि दुश्मन पीछे हट रहा था, तब सरकार

पबी दर्शन सिंह के रूप में हुई है। एक व्यक्ति दर्शन सिंह घायल है और उपचार के लिए मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर वासियों ने डर के साए में पूरी रात काटी। सुबह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक सदर अनिल शर्मा, नगर निगम के मेयर वीरेंद्र भट्ट, कमीशनर रोहित राठौर और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

नेहरू,इंदिरा और मेरी मां के आंसुओं पर बात की

पर युद्ध क्यों रोका ये नहीं बता पाए-प्रियंका

नई दिल्ली। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने अपने भाषण में नेहरू, इंदिरा गांधी और मेरी मां सोनिया गांधी के आसुओं की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि संघर्ष के बीच अचानक ऑपरेशन क्यों रोक़ा गया? प्रियंका ने सवाल उठाया कि दुश्मन पीछे हट रहा था, तब सरकार



ने सीजफ़ायर का फैसला क्यों लिया और देश को इसकी वजह क्यों नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरी सवालों से बच रही है और केवल भावनात्मक बातें करके जनता का ध्यान भटका रही है।



पटना में बारिश के बाद जलभराव वाली सड़क से गुजरते यात्री।

संसद में बोले अमित शाह ने बताया

पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकी मोर गए

नई दिल्ली। एजेंसी

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले तीन आतंकवादी ‘ऑपरेशन महादेव’ के तहत मारे जा चुके हैं। उन्होंने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए यह जानकारी दी। शाह ने कहा, “मैं सदन के माध्यम से, कल हुए ‘ऑपरेशन महादेव’ की जानकारी

पूरे देश को देना चाहता हूँ। कल ‘ऑपरेशन महादेव’ में सुलेमान, अफ़मान और जिब्रान नाम के तीन आतंकवादी जम्मू, सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त अभियान में मारे गए। उन्होंने बताया, “सुलेमान, लश्कर-ए-तैयबा का ए श्रेणी का कमांडर था। पहलगाम और गगनगौर आतंकी हमले में वह लिप्त था, इसके बहुत सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास हैं। अफ़मान और जिब्रान भी ए श्रेणी के आतंकवादी

थे। गृह मंत्री ने कहा, “जिन्होंने पहलगाम की बैसरन घाटी में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा था, उनमें ये तीनों आतंकवादी शामिल थे और कल तीनों ही मारे गए। मैं सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के सभी जवानों को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। गृह मंत्री के अनुसार, बीते 22 अप्रैल को दिन में एक बजे पहलगाम की बैसरन घाटी में हमला हुआ था और वह शाम



5.30 बजे श्रीनगर पहुंच गए थे तथा 23 अप्रैल को एक सुरक्षा बैठक की गई और इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई कि नृशंस हत्या करने वाले हत्यारे देश छोड़कर भागने न पाएं। उन्होंने बताया कि पूरी छानबीन के

बाद यह पुष्टि की गई कि इन तीनों आतंकवादियों ने ही 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। गृह मंत्री ने कहा, “आज मैं सदन को यह बताते हुए बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के आकाओं को जमीन में मिला देने का काम किया था और सेना एवं सीआरपीएफ ने उन आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने

कटाक्ष करते हुए कहा, “मुझे अपेक्षा थी कि जब ये (विपक्ष) पहलगाम हमले के आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सुनेंगे तो खुश होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये (विपक्ष) इससे खुश नहीं हैं। यह किस तरह की राजनीति है? शाह ने इस बात पर जोर दिया, “ये हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, तीनों की साझा तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए।

संपादकीय

दुनिया भर में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर प्रौद्योगिकी के विकास में नई-नई मिसाल कायम की जा रही हैं। इसी का दंभ भरकर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज करने या फिर भविष्य में चांद पर बस्ती बसाने के दावे भी किए जा रहे हैं। मगर, क्या वास्तव में विकास का पैमाना यही है? समाज के समग्र उत्थान का तत्त्व विकास की इस धारा में कहाँ है? यह कैसा विकास है कि एक तरफ विभिन्न देश तकनीक के बूते खुद के ताकतवर एवं

साधन संपन्न होने का राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी ओर दुनिया में करोड़ों लोग भुखमरी के कारण अपने शरीर की ताकत भी खो रहे हैं।विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की ‘वैश्विक खाद्य संकट’ पर एक हालिया रपट में किए गए खुलासे चिंताजनक है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में उनतीस करोड़ से अधिक लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं, जहां उनके लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल है। साफ है कि समाज का सबसे कमजोर तबका आज भी संघर्ष, महंगाई, प्राकृतिक आपदा और

जबरन विस्थापन जैसी समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है।संसाधनों के अभाव और संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की डगर ज्यादा कठिन हो गई है। रपट में सामने आया है कि 2024 में लगातार छठे वर्ष दुनिया में गंभीर खाद्य संकट और बच्चों में कुपोषण बढ़ा है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष 53 देशों या क्षेत्रों के 29.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे थे। यह आंकड़ा वर्ष 2023 के मुकाबले 1.37 करोड़ अधिक है। यानी सुधार के बजाय स्थिति

पहले से कहीं अधिक खराब हो गई है। भुखमरी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें दो देशों के बीच युद्ध और आंतरिक संघर्ष प्रमुख हैं।भूख, भुखमरी और भोजन का संकट, एक अरब आबादी की जरूरत का खाना रोजाना हो रहा बर्बाद।इन दो कारणों से ही बीस देशों में करीब 14 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। जाहिर है, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों की वजह से हालात और ज्यादा बदतर हो रहे हैं। युद्ध के दौरान प्रभावित लोगों को राहत के तौर पर खाद्य सामग्री पहुंचाने पर रोक लगा देने की

खबरें भी आती रहती हैं। इस तरह के प्रयास वास्तव में मानवीय संवेदनाओं के दम तोड़ देने की ओर इशारा करते हैं।महंगाई और बेरोजगारी से उपजी विकट आर्थिक स्थितियां भी भुखमरी के लिए जिम्मेदार हैं। रपट में कहा गया है कि इन दोनों कारणों से पंद्रह देशों में 5.94 करोड़ लोगों का जीवन संकट में है।

इसके अलावा, सूखा और बाढ़ ने 18 देशों में 9.6 करोड़ लोगों को खाद्य संकट में धकेल दिया है। इस पर तुरा यह है कि इन लोगों को खाद्य एवं पोषण सहायता के लिए मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मदद में भी भारी गिरावट आई है। ऐसा लगता है कि वैश्विक भूद और राजनीतिक इच्छाशक्ति की सांसें धीरे-धीरे उखड़ रही हैं। ऐसे में जबरन विस्थापन भुखमरी के संकट को और बढ़ा रहा है।

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ऐसे दूरगामी वैश्विक असर पड़ेंगे

(कमलेश पांडे)

आंकड़े बताते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच पुराने व्यापारिक रिश्तों के बावजूद 2023-24 में केवल 21.34 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। जो दोनों देशों के अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए यह आंकड़ा बहुत कम है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) केंद्र में सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अंतरराष्ट्रीय मायने बेहद अहम हैं, क्योंकि इसका फायदा दोनों देशों के अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा। इस प्रकार भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आने वाले वर्षों में दूरगामी वैश्विक असर भी देखने को मिलेंगे।

यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका प्रेरित भूमंडलीकरण और निजीकरण की नीतियों पर आधारित मुक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौरान, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से कारोबारी संरक्षणवाद बढ़ा है, उसमें ऐसे व्यापार समझौतों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। देखा जाए तो भाजपा नीत एनडीए सरकार ने 2014 में केंद्रीय सत्ता में आने के बाद भारत ने मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है।

लिहाजा, भारत-ब्रिटेन में बीच हुआ एफटीए उसी की एक अगली कड़ी है। जबकि यूरोप से हमारी बातचीत जारी है, जिसे जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अर्थव्यवस्था (इकॉनमी) के मोर्चे पर आने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने में ऐसी ही द्विपक्षीय व्यापारिक डील सहायक होती है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच पुराने व्यापारिक रिश्तों के बावजूद 2023-24 में केवल 21.34 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। जो दोनों देशों के अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए यह आंकड़ा बहुत कम है। लिहाजा माना जा रहा है कि ट्रेड डील से सालाना व्यापार 34 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा। जबकि दोनों देश साल 2030 तक इसे 120 बिलियन डॉलर की ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं।

इससे साफ है कि अब दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और कारोबारी संतुलन लाने में भी आशातीत मदद मिलेगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आधुनिक भारत के निर्माण में इंग्लैंड का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 1947 से पहले इंडिया पर उसी का शासन था। कॉमनवेल्थ देशों के सदस्य के नाते उससे भावनात्मक लगाव भी है। देखा जाए तो इस समझौते को लेकर लंबे समय से भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी। इसकी वजह से ही अमेरिका की टैरिफ सम्बन्धी बातचीत भी चल रही थी और हाल में ही इसमें भी तेजी आई है। इसके पीछे एक

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता: एक क्रांतिकारी कदम

(ललित गर्ग)

मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में जिस प्रकार से गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता पर जोर दिया, उसी का परिणाम है यह करार। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि अब भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए विश्व से संवाद करता है।

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की अंतिम स्वीकृति ने न केवल वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य को भी एक नई दिशा दी है। दोनों देशों के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का फायदा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से संरक्षणवाद बढ़ा है, उसमें ऐसे व्यापार समझौतों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इस समझौते से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देशों को भी भारत की मजबूत होती स्थिति का आडना दिखाया है, जो उनकी दूरगामी एवं कूटनीतिज्ञ राजनीति का द्योतक है। इस समझौते को मौजूदा दौर में दुनियाभर में जारी बहुस्तरीय तनाव, दबाव एवं दादागिरी की राजनीति के बीच एक बेहतर एवं सुझबूझभरी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। यह छिपा नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुल्क के मोर्चे पर एक बड़ा दंष्ट्र एवं संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन भारत ने इस दंष्ट्र के बीच झुकने की बजाय नये रास्ते खोजे हैं। निश्चित ही यह व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीडीटीए) महज एक कागजी करार नहीं, बल्कि ‘विकसित भारत 2047’ के स्वप्न को मूर्त रूप देने की ठोस रणनीति है। जहां एक ओर यह समझौता 99 प्रतिशत टैरिफ को समाप्त कर वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, कृषि व रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को नई उड़ान देगा, वहीं दूसरी ओर छोटे उद्यमों, मछुआरों और किसानों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाएगा। भारत के ग्रामीण अंचलों से हल्दी, दाल, अचार जैसे उत्पाद अब ब्रिटिश बाजारों में अपनी महक फैलाएंगे।

मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में जिस प्रकार से गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता पर जोर दिया, उसी का परिणाम है यह करार। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि अब भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए विश्व से संवाद करता है। यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह सेवा क्षेत्र, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, निवेश, सामाजिक सुरक्षा, और दोहरे करधान जैसे क्षेत्रों में भी भारतीयों के लिए नए दरवाजे खोलता है। खासकर ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए यह राहत का संदेश

है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिल सकेगी। यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब तक अमेरिका की ओर से पैदा किये गये किसी दबाव के आगे भारत ने झुकना स्वीकार नहीं किया और उसने भारत-ब्रिटेन जैसे नये विकल्पों को खड़ा

मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनाने की संकल्पना से जुड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने भारत को तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने के अपने संकल्प में नये पंखों को जोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को



करने और पुराने को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाये हैं।

ब्रिटेन के साथ यह एफटीए एक उदाहरण है कि कैसे भारत न्यायसंगत और समावेशी व्यापार समझौते कर सकता है, जिसमें न तो अपने किसानों, न ही डेयरी क्षेत्र या छोटे उत्पादकों को नुकसान होता है। भारत ने संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखकर आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा की अपनी नीति को बरकरार रखा है। वर्तमान में भारत का वैश्विक व्यापार लगभग 21 अरब डॉलर है, जो इस समझौते के बाद 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना रखता है। यह न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि भारत की मैनुफैक्चरिंग हिस्सेदारी को 17 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने में सहायक होगा। इस करार के साथ, मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि जब नियोजित दृष्टिकोण, वैश्विक प्रतिष्ठा और साहसिक निर्णय साथ चलते हैं, तो भारत जैसे विकासशील देश भी वैश्विक मंच पर निर्णायक बन सकते हैं।

भारत और ब्रिटेन के बीच सीडीटीए के अस्तित्व में आने से एक नये आर्थिक सूर्य का उदय हुआ है, जिससे रोजगार सहित अनेक उन्नत राष्ट्र-निर्माण के अवसर सृजित होंगे। सीडीटीए की संकल्पना आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के अनुरूप ही है। यह

फिर से स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में है। ऐसे समझौते व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं। पिछली यूपीए सरकार ने भारत के व्यापारिक दरवाजे प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए खोलकर भारतीय व्यवसायों को खतरे में डालने वाला रवैया अपनाया था, लेकिन अतीत की उन बड़ी भूलों को सुधारा जा रहा है, जो नये भारत-विकसित भारत का आधार है।

मोदी के मेड इन इंडिया संकल्प की दृष्टि से यह डील बेहद अहम है। इससे करीब 99 प्रतिशत निर्यात यानी यहां से ब्रिटेन जाने वाली चीजों पर टैरिफ से राहत मिलेगी। इसी तरह ब्रिटेन से आनी वाली चीजें भारत में सस्ती मिल सकेंगी। जिससे आम लोगों को अधिक गुणवत्ता वाला सामान सस्ते में सुलभ होगा और जीवनस्तर में व्यापक सुधार होगा। डील से एक बड़ा फायदा होगा टेक्सटाइल्स, लेंदर और इलेक्ट्रॉनिक्स को। इनसे मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। अभी ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.8 प्रतिशत है, जबकि चीन की 28.8 प्रतिशत। इसी तरह, देश की जीडीपी में मैनुफैक्चरिंग का योगदान 17 प्रतिशत है और सरकार इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती

वहां कृषि और डेयरी प्रॉडक्ट्स को लेकर रस्साकशी है। अमेरिका इन दोनों क्षेत्रों में खुली छूट चाहता है, जबकि अपने लोगों के हितों को देखते हुए भारत ऐसा नहीं कर सकता। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार होने से भारत के कृषि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

क्रांतिकारी सुधारों, नवाचार, तकनीक, कारोबारी सुगमता और प्रधानमंत्री के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आर्थिक सूरज के रूप में उभारने में मदद की है, जहां विपुल संभावनाएं हैं। आज दुनिया भारत की ओर आशाभरी नजरों से देख रही है और भारत की अद्भुत विकासगाथा का हिस्सा बनना चाहती है। प्रमुख देशों द्वारा एक के बाद एक एफटीए इसी मान्यता की पुष्टि करते हैं। ब्रिटेन के साथ यह व्यापार समझौता बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के एफटीए वस्तुओं और सेवाओं से कहीं आगे तक सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं नागरिक हितों तक जाते हैं। आस्ट्रेलियाई एफटीए के साथ भारत ने दोहरे करधान का मुद्दा सुलझाया, जो आईटी कंपनियों की परेशानी बढ़ा रहा था। ब्रिटेन के साथ समझौते का एक अहम बिंदु दोहरे अंशदान से जुड़ा है। यह ब्रिटेन में नियोक्ताओं, अस्थायी भारतीय कर्मियों को तीन वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

नागरिक बोध और नज़ीर बनता इंदौर

प्रो. मनोज कुमार

मध्यप्रदेश हमेशा की तरह स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे आगे रहा. लगातार 8वीं दफा इंदौर सिरमौर बना तो राजधानी भोपाल भी श्रेष्ठता का सिरमौर बना. मध्यप्रदेश के कुछ अन्य शहर भी स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वयं को साबित किया। स्वच्छता सर्वेक्षण का यह परिणाम सचमुच में सुखदायक है और गर्व से कह सकते हैं कि देश का दिल मध्यप्रदेश अब एक स्वच्छता प्रदेश भी है। अब सवाल यह है कि पुरस्कारों का ऐलान हुआ, उत्सव हुआ, चर्चा हुई और असली मकसद स्वच्छता फिर कहाँ तक तक के लिए हाशिए पर जाता दिख रहा है जब तक दुबारा स्वच्छता स्वच्छता सर्वेक्षण का सिलसिला आरंभ ना हो। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या हम सिर्फ नम्बरों में आगे रहने के लिए ही स्वच्छ प्रदेश होने का प्रयास करते हैं या नागरिक बोध के साथ स्वच्छता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं? पिछले सालों का अनुभव यही बताता है कि हमारी रूचि निरंतर स्वच्छ बने रहने से ज्यादा स्वच्छता सर्वेक्षण में सिरमौर बने रहने की है. स्वच्छता उत्सव चार दिनों का ना होकर पूर्ण नागरिक बोध से हो तो यह स्वच्छता का नम्बरों का यह खेल एक दिन थम भी जाए तो हम गौरव से स्वयं महसूस कर सकें कि हम स्वच्छ प्रदेश के वासी

हैं. लेकिन ऐसा करने वालों में एकमात्र शहर मध्यप्रदेश ही नहीं, देश में रहने वाला इंदौर है. पूर्ण नागरिक बोध के साथ इंदौर के नागरिक अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं. इस बात पर कुछ लोग एतराज कर सकते हैं कि ये क्या बात हुई लेकिन सच यही है. इंदौर क्यों नागरिक बोध से भरा हुआ शहर है, यह जानना है तो उसकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना होगा. राजनीति तो राजनीति होती है और सत्ता और शीर्ष पर बने रहने के लिए कुछ भी करेगा की नीति पर चलती है लेकिन आप जब इस पर विशेषण करेंगे तो पाएंगे कि इन सबके बावजूद इंदौर की राजनीति इससे परे है और तब जब अपने शहर इंदौर की बात हो. इंदौर की अस्मिता और प्रतिष्ठा को लेकर सभी निर्दलीय हो जाते हैं. स्वच्छता को लेकर, नागरिक सुविधाओं को लेकर भी इंदौर का यही चरित्र रहा है. कदाचित्त कभी, कहीं इंदौर की स्थानीय राजनीति फेल हुई तो नागरिक इसका जिम्मा उठा लेते हैं. स्वच्छता सर्वेक्षण का सिलसिला जबसे आरंभ हुआ है, बच्चा-बच्चा स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझता है. शहर के वाशिंगें हों या शहर में आए मेहमान, उन्हें भी इंदौर की स्वच्छता की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है. एक कागज़ का

टुकड़ा भी गलती से सड़क पर फेंक दिया तो ना जाने कहाँ से कोई आएगा और आपसे कहेगा- भिया यहां नहीं. और वो खुद उस कचरे को उठाकर डस्टबीन में डाल देगा. आमतौर पर निगम के स्वच्छता साधियों के बारे में राय है कि वे अपने काम के प्रति संजीदा नहीं होते हैं. इस सोच पर इंदौर के निगम के स्वच्छता साथी थपड़ मारते हैं. वे स्वच्छता की जिम्मेदारी नौकरी के भाव से नहीं करते हैं बल्कि वे नागरिक बोध से भरकर इस जिम्मेदारी को सम्हालते हैं, पूरा करते हैं। यह बात सबसे सुंदर और सीखने वाली दूसरे शहरों के लिए है. स्वच्छता में सिरमौर बनने के लिए पहले और अभी के अफसरों में होड़ मची होती है कि उनके कार्यकाल के कारण इंदौर को यह कामयाबी मिली लेकिन वे भूल जाते हैं कि जिस शहर में नागरिक बोध ना हो, वहाँ व्यवस्था भी फेल हो जाती है. सिस्टम का काम बजट और सुविधा मुहय्या कराना है और उसकी मॉनिटरिंग करना लेकिन कार्य व्यवहार तो नागरिक बोध से ही आता है. कलश को श्रेय देने के बजाय बुनियाद को प्रणाम किया जाए तो इंदौर हमेशा स्वच्छ शहर बना रहेगा.

इंदौर को बार-बार स्वच्छता में श्रेष्ठता क्यों हासिल होती है, इस पर आपत्ति हो सकती है

जिसका जवाब ऊपर लिखा जा चुका है. अब बड़ा सवाल यह है कि इंदौर जैसा नागरिक बोध अन्य शहरों में क्यों नहीं है? क्यों वहाँ पर इस बात की चिंता नहीं की जाती है कि इंदौर की तासीर में हम क्यों ना घुलमिल जाएँ. दूसरे शहरों में भी शहर को स्वच्छ रहने के लिए बजट और सुविधा आवंटित होता है लेकिन वह रूटीन में निपटा दिया जाता है. स्वच्छता सर्वेक्षण के समय जरूर दबाव रहता है कि हमें पुरस्कार जीतना है, सबसे आगे रहना है तो जाहिर है कि कागजी कार्यवाही पूरा कर कुछ पुरस्कार और नंबर पा लेते हैं. तमाम विषयों को लेकर शहर-दर-शहर विमर्श, गोष्ठी और संवाद का सिलसिला चलता है लेकिन शायद ही कहीं स्वच्छता पर विमर्श को लेकर संवाद का कोई सिलसिला शुरू हुआ हो. आमतौर पर हमारी मानसिकता है कि यह काम सरकार का है, नगर निगम का है, वो करे. इस मानसिकता के साथ हम कागजी तौर पर स्वच्छ शहर का तमगा तो पहन सकते हैं लेकिन खुद से सच का सामना नहीं कर सकते हैं.

यह हाल देश के सभी शहरों और राजधानी का है. स्वच्छता में सिरमौर बनने की दौड़ में शामिल शहरों की पोल हर बार बारिश खोल देती है और इस बार भी यही हो रहा है. सड़कें

और नालियाँ बजबजा गई हैं. पॉलिथीन और दूसरे कचरों से पानी निकासी की व्यवस्था चरमरा गई है. कम से कम उन शहरों से यह सवाल किया जा सकता है कि आप तो स्वच्छता सर्वेक्षण में सिरमौर रहे हैं, फिर ये संकट क्यों उत्पन्न हुआ? मामला साफ है कि हम कागजीतौर पर तो स्वच्छ हो गए लेकिन नागरिकबोध के अभाव में शहर को जमीनीतौर पर स्वच्छ नहीं रख पाए. इंदौर भी इस आरोप से पूरी तरह बरी नहीं है। अगले वर्ष फिर हम स्वच्छता उत्सव मनाएंगे. जिन शहरों के खाते में नंबर आएंगे, उन्हें शाबासी देंगे औ जो पिछड़ जाएंगे, उनसे सवाल किए जाएंगे. यह सब प्रशासनिक प्रक्रिया है, चलती रहेगी. आपके घरों का कचरा उठाने के लिए आने वाली गाड़ी में बजने वाला गीत कहां गुम हो गया? स्वच्छता साधियों को मिलने वाली सुरक्षा में भी ढील है, आखिर इसका दोषी कौन? मूल प्रश्न यह है कि स्वच्छता के लिए देश के हर नागरिक में अपने शहर के प्रति नागरिक बोध का भाव हो. नियमित रूप से स्वच्छता पर चर्चा, संवाद, संगोष्ठी हो. अपने शहर की अस्मिता और प्रतिष्ठा के लिए नागरिक जागरूकता, नागरिक बोध सर्वप्रथम है ताकि स्वच्छता उत्सव चलता रहे.(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया शिक्षा से संबद्ध हैं)

(वैज्ञानिक-स्तर), अरुण एस. सूर्यवंशी (वैज्ञानिक-ध्व), पी. कपीधर (वैज्ञानिक-ध्व 1), डॉ. अमित दुबे (वैज्ञानिक-ध्व), श्री अश्विनेश त्रिपाठी (वैज्ञानिक-ध्व) ने विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर आयोजित रंगोली व पोस्टर प्रतियोगिता में स्कूल एवं कॉलेज स्तर के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणपत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की समस्तता में प्रमुख भूमिका निभाई महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. वीणा त्रिपाठी, डी.आर. साहू, डॉ. डी.डी.डी. द्विवेदी, डॉ. संध्या बघेल, जितेन्द्र बारसे, दुर्गा प्रसाद जघेल, सुश्री श्वेता साहू, बी.आर. साहू, डॉ. राजकुमार त्रिपाठी, श्रीमती ज्योति गेंदे, डॉ. पायल गोस्वामी, अविनाश अंगलावे, आशुतोष शुक्ला, एवं समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ ने। कार्यक्रम जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र-छात्राओं की भागीदारी ने इस आयोजन को ज्ञान और प्रेरणा का उत्सव बना दिया।

